vkj- ,u- vkbZ- ua- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 15 vad % 18 y[kuÅ] c)okj 14 vxLr 2024 ls 20 vxLr 2024 rd i"B&8 ewY; % ,d :i;k

साढ़े सात साल में साढ़े छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही योगी सरकार

लखनऊ। लोकभवन सभागार में मंगलवार को नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ

सेवा चयन आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। नियुक्ति पत्र पाकर किसी अभ्यर्थी ने अपने पिता के सपने के पूरा होने की बात बताई तो किसी ने अपने परिश्रम की कहानी सुनाई। ज्यादातर अभ्यर्थियों की जुबां पर २०१७ के बाद से सरकारी नौकरियों में आई पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सीएम योगी के प्रति आभार था। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी एवं रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। स्वयं सीएम योगी अधिकारियों से विभागों में रिक्त हुए पदों की बराबर जनकारी लेते रहते हैं और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का समय–समय पर निर्देश भी देते हैं। इसी का परिणाम है कि योगी सरकार विगत साढ़े सात साल में साढ़े छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। यहीं नहीं, संविदा के माध्यम से ३.७५ लाख से अधिक युवाओं को नौकरी से जोड़ा गया है। साथ ही दो करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी का नतीजा है कि २०१६ में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर १६ प्रतिशत थी, वो घटकर २.४ रह गई है। सीएम योगी के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद राज्य मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुईं वाराणसी की दीप्ति राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बहुत–बहुत धन्यवाद। १५ अगस्त से पहले उन्होंने हम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दीप्ति ने कहा कि पूरी भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हुई है। मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुए प्रतापगढ़ के रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती परीक्षाएं किसी न किसी वजह से फंस जाती थीं। उनका परिणाम नहीं आ पाता था, लेकिन सीएम योगी के शासनकाल में समय पर परीक्षा और परिणाम आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। मंडी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त हुए अंकित गुप्ता का कहना है कि यह भर्ती बिना किसी लेनदेन के संपन्न हुई है। इसकी परीक्षा में पूरी शुचिता एवं निष्पक्षता का पालन किया गया है। उन्होंने सीएम योगी का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

खटाखट-फटाफट वाले हो गए गायब, चुनावी मौसम में आएंगे नजरः योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पर इशारों–इशारों में जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल–मई के महीने में आपने 'खटाखट स्कीम' के बारे में सुना होगा, लेकिन अब लोगों का कोई अता पता नही हैं। उन्होंने कहा कि अब ये लोग फिर से चुनावी मौसम में नजर आएंगे। अपना हमला जारी रखते हुए योगी ने कहा कि लोगों से एक–एक लाख रुपये के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने ८५०० रुपये भेजने का वायदा किया गया था, लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता–पता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक गरीब परिवारों की एक महिला के खाते में तब तक एक लाख रुपये डाले जाएंगे, जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा खटाखट आता रहेगा और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन–देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। उन्होंने कहा कि विगत साढ़े सात वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो वह ऐसी सजा देंगे, जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, वह अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना का मामला बंद किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर

दी। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन और अन्य दावे जारी करने से रोकने के उनके वचन को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने १४ मई को अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।

यूपी विधानसभा उप चुनाव में जिम्मेदारी से पीछे हटे राहुल गांधी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की जड़े मजबूत करने में लगे राहुल गांधी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। संभव इसीलिये उन्होंने राज्य की १० विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी पांच सांसदों को तो अलग–अलग विधान सभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। गौरतलब हो, विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस दस सीटों में से पांच पर स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है और पांच सीटें समाजवादी पार्टी के लिये उसने छोड़ने का मन बनाया है। इसी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने पांच सीटों पर अपने सांसदों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति कर दी है। इसी के तहत अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा को सीसामऊ, सांसद इमरान मसूद को मीरापुर, सांसद राकेश राठौर को कुन्दरकी, सांसद तनुज पुनिया को गाजियाबाद व सांसद उज्जवल रमन सिंह को फूलपुर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। जबकि राहुल गांधी चाहते तो फूलपुर विधान सभा क्षेत्र की जिम्मेदारी स्वयं भी संभाल सकते थे। फूलपुर वह सीट है जहां से उनके पर नाना

पंडित जवाहर लाल नेहरू सांसद रह चुके थे। इसी वजह से कांग्रेस आलाकमान ने समाजवादी पार्टी से फूलपुर की सीट की महत्ता को देखते हुए यहां से अपनी पार्टी के लिये समाजवादी पार्टी के सामने दावेदारी पेश की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी इस बात का कोई जबाव नहीं दे पा रहा है कि उप चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कौन सभी भूमिका निभायेगें। बात यहीं तक सीमित नहीं है। भले ही राहुल गांधी ने व यनाड सीट छोड़कर रायबरेली से अपनी सांसदी तय कर ली है, लेकिन यूपी को लेकर राहुल गांधी के दिल की दूरियां कम नहीं हो पा रही हैं। अभी भी उनकी यूपी में कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। वह रायबरेली तक तो फिर भी कभी कधार आ जाते हैं,लेकिन इससे बाहर यूपी में कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। खैर, कांग्रेस आलाकमान ने जहां अपने पांच सांसदों के ऊपर उप चुनाव की जिम्मेदारी डाली है वहीं विधायक को भी फ्री नहीं छोड़ा है। इसी क्रम में कांग्रेस ने विधायक वीरेन्द्र चौधरी को मझवां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कटेहरी, अखिलेश प्रताप सिंह को मिल्कीपुर, राजकुमार रावत को खैर व रामनाथ सिकरवार को करहल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी छह विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है।

सम्पादकीय

अर्थव्यवस्था तो गहरे संकट का शिकार

हिंडनबर्ग रिसर्च ने डेढ़ साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें विदेशों में फर्जी कंपनियां बना कर उनके जरिए शेयरों के भाव कोंत्रिम रूप से बढ़ाने का इल्जाम भी था। ये आरोप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निगरानी और जांच के दायरे में आते थे। तब यह सवाल उठा था कि क्या सेबी अपना काम पूरी तत्परता से नहीं करती है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर विश्वास किया और उसके ही भरोसे पर हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया। अब हिंडनबर्ग ने सीधे सेबी को घेरे में ले लिया है। उसने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप की विदेशी फर्जी कंपनियों में हित रखने का आरोप लगाया है। यानी हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी ग्रुप को संरक्षण देने में बुच दंपति का स्वार्थ था। मतलब यह कि सेबी प्रमुख ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया। जाहिर है, इस आरोप के जरिए भारतीय वित्तीय बाजार की साख संदिग्ध करने की कोशिश की गई है। बड़ा मुद्दा यह है कि जब नियमों के रखवाला ही आरोपों के घेरे में हो, तो संबंधित बाजार पर कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा? यहां ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आज जितनी भी चमक है, वह वित्तीय बाजारों के भरोसे ही है। वरना, जमीनी अर्थव्यवस्था तो गहरे संकट का शिकार है। अब वित्तीय बाजारों पर भी ग्रहण लगा, तो देश के लिए उसके बेहद गंभीर नतीजे होंगे। यह हैरतअंगेज है कि आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हों, या अब सेबी प्रमुख पर, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। आखिर उसका क्या हित इनसे जुड़ा है? यह जरूरी है कि सत्ताधारी दल और केंद्र सरकार ऐसे मामलों में निष्पक्ष भूमिका अपनाएं। उन्हें विपक्ष की इस मांग को स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए कि सारे प्रकरण की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति करे। इससे अडानी ग्रुप और बुच को भी ऐसा मंच मिलेगा, जहां उनकी दी गई सफाई पर देश गौर करेगा। वरना, गहराते संदेह का राहु भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रसता ही जाएगा।

अखिलेश यादव ने सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने की मांग की

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सोमवार को सरकार से इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाने की मांग की। यादव ने एक्स पर कहा, कोई भी समुदाय चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिये वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म–पंथ–मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसी पोस्ट में कहा, भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। सपा अध्यक्ष ने इससे पहले एक्स पर ही बांग्लादेश का नाम लिये बगैर कहा था कि देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास सिखाता है कि जो सरकार किसी और देश के राजनीतिक हालात का इस्तेमाल अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए करती है, वह देश को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर कमजोर करती है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, विश्व इतिहास गवाह है कि कई देशों में विभिन्न कारणों से, सही या गलत, उस समय के हालातों के अनुसार, हिंसक जन क्रांतियां,

सैन्य तख्तापलट, सत्ता–विरोधी आंदोलन होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उथल–पुथल भरे समय में केवल उसी देश का पुनरुत्थान हुआ है, जिसने किसी के खिलाफ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सपा अध्यक्ष ने कहा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर, एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी–पड़ोसी की रक्षा करना भी हर सभ्य समाज का मानवीय–दायित्व होता है, फिर वह चाहे किसी काल–स्थान–परिस्थिति में कहीं पर भी हो। उन्होंने कहा कि कई बार किसी देश के आंतरिक मामलों से प्रभावित होने वाले किसी अन्य देश का एकल स्तर पर हस्तक्षेप करना वैश्विक राजनयिक मानकों के लिहाज से उचित नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे में उस प्रभावित देश को अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी मूक विदेश नीति को सक्रिय करते हुए, विश्व बिरादरी के साथ मिलकर साहसपूर्ण सकारात्मक मुखर पहल करनी चाहिए। जिससे सार्थक समाधान निकल सके। उन्होंने कहा कि जो सरकार ऐसे में मूक–दर्शक बनी रहेंगी, वे ये मानकर चले कि ये उसकी विदेश नीति की नाकामी है, क्योंकि उसके सभी दिशाओं के निकटस्थ देशों में परिस्थितियां न तो सामान्य हैं और न उसके अनुकूल। सपा प्रमुख ने कहा, "इसका मतलब है कि 'भू–राजनीतिक' नजरिये से उसकी विदेश नीति में कहीं कोई भारी चूक हुई है। सांस्कृतिक–निकटस्थता के सूत्र से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को बांधकर आपसी समझबूझ और भाईचारे से ही विश्व के विभिन्न अशांत भू–खंडों में अमन–चौन लाया जा सकता है। अखिलेश ने कहा कि सकारात्मक सोच से उत्पन्न सौहार्द एवं शांति ही मानवीय समृद्धि का मार्ग है।

शुरू हुआ मुकदमों का ट्रायल, इलाहाबाद HC की सिंगल बेंच कर रही सुनवाई

लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मुकदमों का ट्रायल आज से शुरू हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। बता दें, हाईकोर्ट ने इस मामले में १ अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की १८ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना

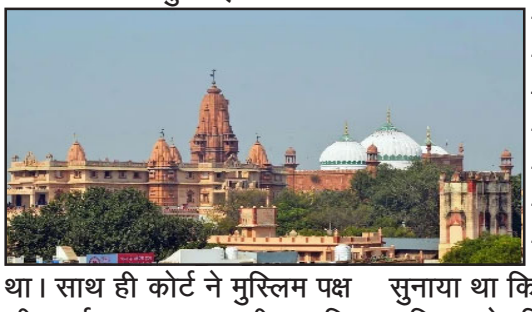

था। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्ज ७ रूल्स ११ की आपत्ति खारिज कर दी थी। हिंदू वादियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है जिसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को चुनौती देता है तो सुनवाई की जाए, जिसने मथुरा में मंदिर–मस्जिद विवाद से संबंधित १८ मामलों की स्थिरता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि यदि दूसरा समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो हिंदू वादियों के खिलाफ कोई एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जाए। एक वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। १ अगस्त को उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद से संबंधित १८ मामलों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, और फैसला सुनाया था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने हिंदू याचिकाकर्ताओं और देवता द्वारा दायर मुकदमों की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उन्हें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१ के तहत प्रतिबंधित किया गया था। अदालत ने कहा था कि हिंदुओं द्वारा दायर सभी १८ याचिकाएं १२ अगस्त से एक साथ पक्ष सुना जाएगा।

दलितों के आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहती हैं मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश में १० विधान सभा सीटों पर होने वाले उप–चुनाव और आरक्षण को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। आरक्षण के नाम पर जिस तरह से बीजेपी सहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता दलितों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सचेत मायावती ने एससीध्एसटी वर्ग के आरक्षण में जातियों का उप वर्गीकरण और क्रिमी लेयर को बाहर करना दोनों खतरनाक बताया है। पहले बात उप–चुनाव की कि जाये तो आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा ने लोकसभा चुनाव के फलस्वरू रिक्त हुई प्रदेश की दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। गत दिवस बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवां, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। मायावती ने कहा कि बसपा गरीबों, शोषितों–पीड़ितों की पार्टी है। सभी मेहनत करें और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में एकजुट रहें। बसपा प्रमुख ने केंद्र व यूपी सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, भाजपा सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन को रोक पाने में विफल रही है। और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके द्वारा विध्वंसक बुलडोजर राजनीति सहित

हर प्रकार का जाति व धार्मिक उन्माद, विवाद पैदा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन पर नया कानून व जाति के आधार पर एससी–एसटी समाज के लोगों का उप–वर्गीकरण की क्रीमी लेयर का नया षड्यंत्र करके उन्हें बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा जाति आधारित गणना से इंकार और मस्जिद–मदरसा संचालन व वक्फ संरक्षण में जबरदस्ती की सरकारी दखलदाजी की जा रही है। चर्चा है कि बसपा ने कटेहरी से प्रतीक पांडेय और फूलपुर से शिवबरन पासी का टिकट फाइनल कर दिया है, हालंकि अधिकांत तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। उधर, दलितों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनैतिक हलचल के बीच मायावती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आरक्षण को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि आरक्षण को पूरा श्रेय बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को जाता है। कांग्रेस के लोगों ने बाबासाहेब को संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा और उन्हें चुनाव में भी हराने का काम किया। इसके साथ–साथ कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को विवश किया। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के बयान में आरक्षण का श्रेय बाबासाहेब डा. भीमराव आंबेडकर को नहीं बल्कि पं. नेहरू व गांधीजी को दिया गया है, जिसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में एससी–एसटी वर्गों के उप–वर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने से पहले उनकी पार्टी एनजीओ व वकीलों से विचार विमर्श करेगी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप–वर्गीकरण के पक्ष में है।

मायावती की मोदी सरकार से मांग, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मामले की हो उच्च स्तरीय जांच

लखनऊ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस से आगे निकल गए हैं और केंद्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होता अगर केंद्र अब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे देता। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि पहले अदाणी ग्रुप व अब सेबी चीफ सम्बंधी हिण्डनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप–प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देशहित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अदाणी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि उबाल पर है। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे यह मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद–विवाद से परे केन्द्र की अपनी साख व विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केन्द्र सरकार को अब तक इसकी उच्च–स्तरीय जाँच अर्थात् जेपीसी या जुडिशियल जाँच जरूर बैठा देनी चाहिये थी तो यह बेहतर होता। अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार देर रात जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

(सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धबल बुच ने बरमूडा तथा म रीशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। उसने कहा कि ये वही कोष हैं जिनका कथित तौर पर विनोद अदाणी ने पैसों की हेराफेरी करने तथा समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विनोद अदाणी, अदाणी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं। आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश २०१५ में किए गए थे, जो २०१७ में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च, २०२२ में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। ये निवेश '' सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से '' किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष ''निष्क्रिय'' हो गए। अदाणी समूह ने भी सेबी प्रमुख के साथ किसी भी तरह के वाणिज्यिक लेन–देन से इनकार किया है। संपत्ति प्रबंधन इकाई ३६०वन (जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता था) ने अलग से बयान में कहा कि बुच तथा उनके पति धवल बुच का आईपीई–प्लस फंड १ में निवेश कुल निवेश का १.५ प्रतिशत से भी कम था और उसने अदाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में नहीं हो सकी सुनवाई, अब २३ अगस्त को अगली पेशी

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी–एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विशेष न्यायाधीश छुट्टी पर थे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख २३ अगस्त तय की गई है। राहुल गांधी २६ जुलाई को अपने खिलाफ मानहानि के मामले में एमपी–एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि यह मामला श्सस्ती लोकप्रियताश हासिल करने के लिए दायर किया गया है। शुक्ला के अनुसार, विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उनके खिलाफ मानहानि का मामला बन सके। अदालत ने सुनवाई की तारीख १२ अगस्त तय की थी। स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने ४ अगस्त, २०१८ को गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक प्रेस क न्फ्रेंस में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने गांधी की टिप्पणी

का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में ष्आरोपीष है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की थी, तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। गांधी की टिप्पणी से करीब चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने २००५ के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था, उस समय वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़ा दी सपा की टेंशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन १० सीटों में से पांच सीटें मांगी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को राज्य में अपनी पांच सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी सीटें पुरानी पार्टी को दी जानी चाहिए। इस बीच, सोमवार को विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में शामिल दोनों दलों ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने–अपने प्रभारियों की घोषणा की। सपा ने छह सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा की, जबकि कांग्रेस ने सभी १० विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कटेहरी सीट के प्रभारी होंगे, जबकि फैजाबाद के सांसद

अवधेश प्रसाद और यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव मिल्कीपुर सीट के प्रभारी होंगे। सांसद वीरेंद्र सिंह को मझवा सीट, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को करहल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज को फूलपुर सीट और विधायक राजेंद्र कुमार को शीशमऊ सीट का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने सांसद किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह को शीशमऊ, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद और फूलपुर सीटों का प्रभारी घोषित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार रावत और पार्टी नेता रामनाथ सिकरवार को क्रमशः मझवां, कटेहरी, मिल्कीपुर, खैर और करहल सीटों का प्रभार मिला है। १० विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिनमें कटेहरी (अंबेडकर नगर), करहल (मैनपुरी), मिल्कीपुर (अयोध्या), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), गाजियाबाद, मझावन (मिर्जापुर), शीशमऊ (कानपुर शहर), खैर (अलीगढ़) , फूलपुर (प्रयागराज), और कुंदरकी (मुरादाबाद) शामिल है।

सपा नेता नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप, आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को सोमवार को १५ वर्षीय लड़की से बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को ११२ हेल्पलाइन नंबर पर लगभग देर रात १.३० बजे एक संकटपूर्ण क ल प्राप्त हुई। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि यह क ल एक युवा लड़की से आई थी जिसने बताया कि उसके कपड़े उतार दिए गए थे और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने लड़की को बचाया और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो ष्आपत्तिजनकष स्थिति में पाया गया। वहीं, नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। भाजपा के अमित मालवीय ने इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी ब्ड कहलाया जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के

रूप में है नवाब सिंह यादव की पहचान। क्या अब भी अखिलेश यादव क्ष्। टेस्ट की मांग करेंगे? यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रदेश में कानून का राज है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उचित कार्रवाई की जाएगी। सपा नेता कथित अयोध्या गैंगरेप की घटना के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे। उन्हें यहां भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह अपनी बुआ के साथ यादव के घर गई थी, उसे बताया गया था कि उसे नौकरी के लिए वहां जाना है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया, ष्बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र करीब १५ साल है।'

समाजवादी पार्टी से संबंध न हों खराब इसलिये कांग्रेस ने टाली लखनऊ रैली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बड़े 'खिलाड़ी' समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्ते खराब नहीं हों इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस फूंक–फूंक कर कदम रख रही है। इसी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लखनऊ में सितंबर माह में प्रस्तावित रैली को अब विधानसभा उपचुनाव तक के लिये स्थगित कर दिया गया है। जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ में रैली करने का निश्चय लिया था। दरअसल, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एनडीए से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से प्रदेश में अपना जनाधार खड़ा करने के लिए राहुल व खरगे की रैली आयोजित की थी। रैली की तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन मौखिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति दे दी थी। कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी को लिये रैली करके सपा से टकराव नहीं लेना चाहती थी,लेकिन कहीं न कहीं वह दबाव की राजनीति बनाये हुए हैं। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में भी पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली से होना है, प्रदेश कांग्रेस ने उन सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है, जिन सीटों पर पिछले विस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। प्रदेश में १० विस सीटों पर विस उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस महसूस कर रही थी कि लखनऊ में कांग्रेस की रैली से प्रदेश में सपा–कांग्रेस गठबंधन मजबूत होगा, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच कुछ अलग थी। सपा नेताओं को लगता था कि कांग्रेस यूपी में पैर पसारने के लिये रैली कर रही है। रैली के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि लखनऊ के रामाबाई आंबेडकर मैदान में रैली के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उपचुनाव के बाद ही रैली रखी जाएगी।

अब छड़ी की जगह ये होगा ओमप्रकाश राजभर की पार्टी का चुनाव चिन्ह, अपना अध्यक्ष भी बदला

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने अपना चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह चाबी रख लिया है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव के बाद से ही चुनाव चिन्ह में बदलाव पर विचार कर रहे थे। वहीं, पार्टी ने प्रेमचंद कश्यप को

सुभासपा की यूपी इकाई का अध्यक्ष बनाया है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी हैं। लोकसभा चुनाव में राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। अरविंद का चुनाव चिन्ह छड़ी था, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तीसरे नंबर पर था। एक एक्स पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयोजन में रविंद्रालय ऑडोटोरियम हाल लखनऊ में आयोजित ष्प्रदेश स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक' में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर प्रदेश पदाधिकारियों एवं २५ जनपदों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की तथा बैठक के पश्चात पार्टी के नये चुनाव चिन्ह 'चाभी' की घोषणा की। राजभर और उनके बेटे का मानना है कि वे चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके मतदाताओं ने गलती से छड़ी के निशान के बजाय नीचे ह की के निशान का बटन दबा दिया था। आज लखनऊ में पार्टी की बैठक हुई जिसमें ओम प्रकाश राजभर को फिर से पार्टी अध्यक्ष चुना गया और पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना चुनाव चिन्ह छड़ी से बदलकर चाबी कर दिया। वहीं, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदेश में मदरसों की मान्यता की नयी व्यवस्था शुरू किए जाने की तैयारी के संकेत देते हुए कहा कि दो विश्वविद्यालय खोलकर मदरसों को उनसे संबद्ध किया जाएगा।

शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की जमानत पर SC में १४ अगस्त को सुनवाई संभव

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता और अन्य की हिरासत २ सितंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों की हिरासत की अवधि तब बढ़ा दी जब उन्हें पहले दी

गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो–कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालाँकि, आम आदमी पार्टी (आप) नेता अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा २०१८ में प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा समाधान निकालने के लिए कुछ और समय मांगे जाने के बाद मामले को छह सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

फिर टला विनेश फोगाट मामले पर फैसला, अब शुक्रवार को निर्णय आने की संभावना

नई दिल्ली। खेल पंचाट ने विनेश फोगाट की रजत पदक अपील पर फैसले को आगे बढ़ा दिया है। निर्णय, जो १३ अगस्त को ६रू३० बजे आईएसटी तक आना तय था, अब १६ अगस्त तक विलंबित हो गया है। निर्णय का समय शुक्रवार को ६रू३० बजे आईएसटी है। हरियाणा की २६ वर्षीय पहलवान ने खेलों से अयोग्य घोषित होने के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले खेल पंचाट (कैस) का तदर्थ प्रभाग ओलंपिक महिला ५० किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य करार दी गईं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर विचार करने पर अभी कुछ और समय लेगा और इसे १३ अगस्त तक टाल दिया गया था। मामले की सुनवाई शुक्रवार को समाप्त हुई जिसमें कैस ने विनेश की अपील स्वीकार कर ली थी। विनेश ने फाइनल मुकाबले की सुबह १०० ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ अपील की थी। इस अपील पर फैसला पहले रविवार शाम सुनाया जाना था। भारतीय

ओलंपिक संघ ने पहले कहा था कि फैसला रविवार को आएगा, लेकिन फिर उसने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि परिणाम १३ अगस्त को ही पता चलेगा। आईओए के बयान में कहा गया, ''सीएएस के तदर्थ प्रभाग ने विनेश फोगाट बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मामले में एकमात्र मध्यस्थ माननीय ड . एनाबेले बेनेट को १३ अगस्त २०२४ को शाम छह बजे तक फैसला देने का समय दिया है।'' इसमें कहा गया है, ''मेरे द्वारा भेजे गए पिछले संचार में ११ अगस्त का संदर्भ सभी पक्षों को एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समय से संबंधित था।'' संस्था ने ''भ्रम और असुविधा'' के लिए माफी मांगी। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह ११ अगस्त को है। विनेश की जगह फाइनल में क्यूबा की पहलवान युस्नेलिस गुजमान लोपेज उतरीं, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थीं। भारतीय पहलवान ने अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिये जाने की मांग की है क्योंकि मंगलवार को अपने मुकाबलों के दौरान उनका वजन निर्धारित सीमा के अंदर था।

अवैध संबंध का शक और उजड़ गया परिवार, दो बच्चों के साथ पत्नी और मां का रेता गला, फिर खुद फंदे से लटका

भागलपुर। बिहार के भागलपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने अपनी कांस्टेबल पत्नी समेत अपने परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी फांसी लगा ली। घटना भागलपुर के पुलिस लाइन में स्थित एक महिला पुलिस अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में हुई। पति को कथित तौर पर शक था कि उसकी कांस्टेबल पत्नी का विवाहेतर संबंध है। उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी, दो बच्चों और मां का गला रेतकर आत्महत्या कर ली। भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) विवेकानंद के हवाले से बताया कि घटना सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात में हुई होगी। स्थानीय लोगों के अनुसार, एक दूधवाले ने खून से लथपथ शवों को देखा और नीतू कुमारी के पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। मृतक कांस्टेबल की पहचान नीतू कुमारी के रूप में हुई है, जबकि उसके पति का नाम पंकज है। कांस्टेबल भागलपुर के एसएसपी कार्यालय में तैनात थीं। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस लाइन में एक महिला पुलिस अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में पांच लोगों के शव मिले हैं। कुमार ने एएनआई को बताया, षजिनमें से ४ लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई और महिला पुलिस अधिकारी के पति का शव छत से लटका मिला।' घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुछ शव बिस्तर पर और कुछ फर्श पर पड़े मिले, जबकि पंकज का शव छत से लटका मिला। कुमार ने बताया कि एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जो महिला पुलिस अधिकारी के पति द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि महिला पुलिस अधिकारी का किसी के साथ अवैध संबंध था। सुसाइड नोट में लिखा था– नीतू ने मेरी मां और दोनों बच्चों को मार डाला। इसके बाद गुस्से में आकर मैंने भी ईंट से कुच–कुच कर नीतू को मारा फिर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर डाली। अब जब मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं भी मरने जा रहा हूं। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लिया. सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

अमेरिका पहुंचे विनय मोहन क्वात्रा, संभाला भारत के नए राजदूत का पदभार

नई दिल्ली। विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने का सौभाग्य मिला है। टीम इंडियन एम्बेसीयूएस इस महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने के लिए गहनता से काम करना जारी रखेगी। क्वात्रा पूर्व विदेश सचिव हैं और तरनजीत सिंह संधू की जगह लेंगे। यहां अपनी आखिरी पोस्टिंग में क्वात्रा भारतीय दूतावास में वाणिज्य मंत्री थे। हालिया दिनों में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा पर अपनी आपत्तियों को उजागर किया। द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने संभवतः बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए क्वात्रा (जो उस समय भारत के विदेश सचिव थे) से बात की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसी सप्ताह आयोजित होने वाला था जब अमेरिका सैन्य गठबंधन के ७५ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन डी.सी. में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नेताओं की मेजबानी कर रहा था। इन चुनौतियों के अलावा, अगले राजदूत पर नए प्रशासन से निपटने का अतिरिक्त बोझ भी हो सकता है, अगर डोनाल्ड जे. ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हाल के सर्वेक्षणों में व्हाइट हाउस की दौड़ में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाढेन से आगे निकल रहे हैं।

सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं... बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर प्रियंका गांधी का पहला रिएक्शन

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों की खबरें परेशान करने वाली हैं और उम्मीद जताई कि वहां की सरकार हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई भी समुदाय चाहे

वह बांग्लादेश का अलग नजरियेवाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म–पंथ–मान्यता माननेवाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को हिंसा प्रभावित देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा की और उन्हें 'जघन्य' करार दिया, और युवाओं से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने का आग्रह किया। ढाका में समुदाय के नेताओं के अनुसार, देश से भागने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं पर हमला किया गया और शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई।

फूलपुर विधानसभा सीट पर दावेदारी को लेकर सपा–कांग्रेस आमने–सामने

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) की जो फूलपुर लोकसभा सीट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की संसदीय सीट हुआ करती थी, उसी के अंतर्गत आने वाली फूलपुर विधान सभा सीट पर होने वाले उप–चुनाव में दावेदारी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ठन गई है। सपा यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है जबकि कांग्रेस इतिहास का वास्ता देकर अपने लिये फूलपुर की सीट मांग रही है। कुल मिलाकर फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तिथि की भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दावेदारी जताने पर सियासत गरमा गई। हालांकि, २४ घंटे के भीतर ही सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यह साफ कर दिया कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, लेकिन फूलपुर उपचुनाव में सपा का ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। बता दें फूलपुर विधान सीट सीट के लिए २०२२ में हुए चुनाव में भाजपा के प्रवीण पटेल ने सपा के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर में कुछ हजार मतों से पराजित किया था। लेकिन वर्ष २०२४ में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर संसदीय सीट से भाजपा ने प्रवीण पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रवीण पटेल चुनाव जीत गए। ऐसे में फूलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। अब यहां उपचुनाव होना है। इंडी गठबंधन से सपा का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा या कांग्रेस का, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। वही सपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगी, लेकिन दूसरे ही पल प्रयागराज आए कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव ने यह कहकर खलबली मचा दी कि गठबंधन की तरफ से कांग्रेस इस सीट पर दावा करेगी। दावे के पीछे कि जो वजह भी बताई गई है उसके अनुसार यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस इकाई द्वारा शीर्ष नेतृत्व के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। बीते लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से अधिक वोट सपा को मिले थे। वर्ष २०२२ में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार मुज्तबा सिद्दीकी कुछ मतों से पराजित हुए थे। ऐसे में इंडी गठबंधन के तहत यह सीट सपा के पास ही है।

संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग,सुप्रीम कोट ने २१ अक्टूबर तक टाली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने की मांग पर सुनवाई २१ अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर विचार करने की जरूरत बताई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन करना उचित है, जिसे बाद में २६ नवंबर १९४९ को स्वीकार कर लिया गया। याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। याचिका में १९७६ में ४२वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि इन शब्दों को शामिल करने से अनुच्छेद ३६८ के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से अधिक है। इससे पहले इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने सवाल किया था कि क्या गोद लेने की तारीख को बरकरार रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से सवाल पूछा था, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। १९७६ में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए ४२वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर कर दिया। एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य।ष्स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि प्रस्तावना को बदला, संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द भारतीय राज्य की अपने नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार आय, धन और अवसर में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगी और संसाधनों का उचित वितरण प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। यह एक विचारधारा के रूप में समाजवाद का कड़ाई से पालन करने का सुझाव नहीं देता है बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह–अस्तित्व में हैं।

दलित वोट बैंक के चक्कर में आरक्षण पर खड़ा कर रहे हैं संशय

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार एसटी–एससी आरक्षण में कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। वहीं एससीएसटी एक्ट के आरक्षण दायरे से इस समाज के क्रिमी लेयर को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने संविधान विरोधी करार देते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया है। इसके बावजूद विरोधी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी को बीजेपी से बड़ा दिखाने के लिये हर वह कदम उठा रहे हैं जिससे उन्हें राजनैतिक फायदा हो सकता है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। उन्होंने कहा कि पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है, तो आरक्षण प्राणवायु। अखिलेश का यह बयान आरक्षण के उप वर्गीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को देखते हुए अहम माना जा रहा है। इससे पूर्व बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कांफ्रेंस करके आरक्षण के भीतर आरक्षण (उप वर्गीकरण) का विरोध करते हुए इस मामले में सपा और कांग्रेस की नीयत भी साफ न होने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने ११ अगस्त को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से नहीं पाटी जा सकती। आरक्षण शोषित, वंचित समाज को सशक्त व सबल करने

का सांविधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा। इसके प्रावधानों को बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है, तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। कुल मिलाकर आरक्षण के सहारे अखिलेश यादव बीजेपी से दो–दो हाथ करके उस दलित वोट बैंक को अपने पास रोके रखना चाहते हैं जो लोकसभा चुनाव में बसपा का दामन छोड़कर उनके साथ आ गया था।

कोचिंग सेंटरों के लिए दिशानिर्देश दोबारा बनाने की मांग, याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोचिंग संस्थानों के लिए, विशेष रूप से आपराधिक दायित्व के संबंध में दिशानिर्देशों को फिर से तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में न केवल अधिकारियों को कोचिंग संस्थानों के लिए

दिशानिर्देशों को फिर से तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई, बल्कि छात्रों को केवल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने के बजाय उनके दिमाग को परिष्कृत करने पर केंद्रित एक शिक्षा प्रणाली के विकास का भी अनुरोध किया गया। यह पुराने राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट की लाइब्रेरी में बाढ़ वाले नाले का पानी घुसने से तीन छात्रों की मौत के बाद हुआ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश पारित करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। "अपनी प्रार्थना देखो. यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. भले ही शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन यह करना हमारे बस की बात नहीं है। यदि शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है, तो उस समय की चुनी हुई सरकार को चुनाव में जाकर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय गैर–लाभकारी संगठन कुटुंब की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह अधिकारियों को दिल्ली में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट आवास चलाने के लिए नियम स्थापित करने का निर्देश दे और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे जो छात्रों के दिमाग को परिष्कृत करने के बजाय उनके दिमाग को परिष्कृत करे। केवल उन्हें प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद करेगा आंदोलन

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद ने केजीएमयू प्रशासन पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा है कि केजीएमयू प्रशासन भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त है कर्मचारियों की पदोन्नति, एसीपी समेत अन्य प्रकरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आन्दोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है, बुधवार सुबह सभी कर्मचारी ओपीडी पर एकत्र होकर अपनी मांग रखेंगे। इस बात की जानकारी केजीएमयू कर्मचारी परिषद ने पत्र जारी कर दी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि केजीएमयू प्रशासन खुद ही चाहता है कि यहां आंदोलन हो और सरकार की छवि धूमिल हो। वहीं इस पत्र के जारी होने के बाद केजीएमयू कर्मचारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कई कर्मचारियों ने कर्मचारी परिषद के कार्यकाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि २८ मई को परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

उसके बाद कार्यकाल बढ़ाने के लिए आम सभा भी नहीं हुई है। उन्होंने मौजूदा परिषद के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल, जून महीने में कर्मचारी परिषद के मंत्री अमित सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे की वजह परिषद का कार्यकाल समाप्त होना बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं परिषद के संविधान एवं सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए कर्मचारी परिषद के मंत्री के पद से अपना त्यागपत्र देता हूँ। इसके बाद से ही कर्मचारी परिषद के चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। इतना ही नहीं फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार को पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गंगवार की तरफ से पत्र लिखकर कर्मचारी परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की शिकायत की गई थी। जिस पर फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार ने परिषद के अध्यक्ष को अपना पक्ष रखने को कहा था। हालांकि कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह ने इन सभी बातों को निराधार करार दिया है।

डॉक्टर रेप-मर्डर केसः रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश

लखनऊ। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना से डाक्टरों में आक्रोश है। जिसका असर मंगलवार को केजीएमयू, लोहिया संस्थान और एसजीपीजीआई में देखने को मिला है। सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज ही वापस लौटना पड़ा है। केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार को ओपीडी में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही

उन्होंने वहां मरीजों को इलाज दे रहे डॉक्टरों से भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के मुख्य गेट पर बैठ गये। जिससे मरीज ओपीडी में नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे मरीजों का इलाज बाधित हो रहा था। हालांकि बहुत से मरीज पुरानी ओपीडी के रास्ते अंदर पहुंचने में सफल रहे, लेकिन उनमें से भी कई मरीजों को बिना इलाज ही वापस लौटना पड़ा है। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना था कि वह इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं कर रहे हैं लेकिन ओपीडी में वह सेवाएं बंद कर रहे हैं। बाद में केजीएमयू की ओपीडी में मरीजों के नये पर्चे बनाये गये। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह का कहना है कि जो मरीज ओपीडी के अंदर आ गए थे उन्हें इलाज दिया गया है। वहीं लोहिया संस्थान में ११ बजे के बाद इलाज पूरी तरह से ठप हो गया और मरीजों को ओपीडी से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं कई मरीजों ने बताया कि काउंटर पर तले डाल दिये गये। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना के दृष्टिगत लोहिया संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर संस्थान के प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी की है। सुबह ११:३० बजे के बाद संस्थान की ओपीडी सेवाएं बाधित रही, लेकिन भर्ती मरीजों को इलाज मुहैया कराया गया। वहीं संस्थान में करीब १५ सर्जरी इस हड़ताल की वजह से टालनी पड़ी है। एसजीपीजीआई में प्लान की गई सर्जरी को ड क्टरों ने टाल दिया है। यहां रेजिडेंट ड क्टरों के समर्थन में फैकेल्टी ने काला फीता बांधकर मरीजों का इलाज किया है, लेकिन ओपीडी में आये मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हड़ताल की वजह से बहुत से मरीजों का पर्चा ही नहीं बन पाया, जिससे पहली बार एसपीजीआई पहुंचे मरीजों को वापस लौटना पड़ा। यहां पर शाम को रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला और कोलकाता के आरजी कॉलेज में दरिंदगी का शिकार हुई परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के मुताबिक महिला डॉक्टर के मामले में आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सेंटर प्रोटैक्शन एक्ट लागू है। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल क लेज में ड्यूटी के दौरान एक परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के बाद से ड क्टरों में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल के इस सरकारी अस्पताल के सेमीनार हॉल में बृहस्पतिवार रात को ३२ वर्षीय ड क्टर का शव अर्द्ध नग्न हालत में मिला था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जांच मंगलवार को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि केस डायरी आज शाम तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए और अन्य सभी दस्तावेज बुधवार सुबह १० बजे तक उसे सौंपे जाएं। सरकारी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था, जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय ने राज्य में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की और कहा कि उनके ऊपर (चिकित्सकों पर) 'पवित्र दायित्व' है।

बुलंदशहर में कृषि विकास अधिकारी बच्ची और बकरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले के अहमदनगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में सरकारी कर्मचारी ने १० वर्षीय दलित लड़की और बकरी से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि घटना १२ अगस्त को शाम को हुई। आरोप है कि कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) के पद पर तैनात गजेंद्र सिंह ने एक दलित व्यक्ति के घर जाकर उसकी बेटी और एक बकरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पूरी हरकत पास में खड़े एक बच्चे ने मोबाइल फोन में रिक र्ड कर ली। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुमार ने बताया कि आरोपी को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट

महराजगंज। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महराजगंज जनपद के भारत-नेपाल ब र्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती हुई है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। १५ अगस्त के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महराजगंज पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने कहा स्वतंत्रता दिवस के ष्टिगत पूरे जनपद की सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रही है। सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहे हैं, प्राथमिक उद्देश्य सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर है। दरअसल, पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ी हुई सीमा खुली होने की वजह से यहां पर घुसपैठ की ज्यादा आशंका रहती है। जिसके कारण महराजगंज से लगे सोनौली और ठूठीबारी सीमा पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस और एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। नेपाल सीमा पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पगडंडी रास्तों पर सादे कपड़ों में जवान भी मौजूद हैं। सीमा के नजदीक के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। भारत आने वाले सभी गाड़ियों और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और गहनता से जांच की जा रही है। बता दें बीते दिनों चार अप्रैल को सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तीन संदिग्धों को पकड़ा था। इनमें से दो पाकिस्तान और एक जम्मू-कश्मीर का निवासी था। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी कोई चूक नहीं करना चाहती।

शक्ति भवन पर बेरोजगार युवाओं का जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली विभाग में नौकरी की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि विद्युत विभाग में **JE**, **AE** और **Technician Grade** २ समेत अन्य टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां पहले विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी। लेकिन **UPPCL** की ओर से ७ अगस्त २०२४ को एक नोटिस जारी करके ये जानकारी दी गई कि अब सरकार ने उन सभी भर्तियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (**UPSSSC**) और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (**UPPSC**) के जरिए कराने की तैयारी में हैं। वहीं युवाओं ने **UPSSSC** पर परीक्षाओं को समय पर संपन्न न कराने और सालों तक लंबित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि **UPSSSC** आयोग की ओर से कराई गई ३० से ज्यादा भर्तियां अभी भी लंबित हैं। किसी की परीक्षा नहीं हुई तो किसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वहीं विद्युत सेवा आयोग की ओर से पूर्व में कराई गईं सभी भर्तियों की समय से परीक्षा हुई है और समय से भर्तियां संपन्न की जाती रही है।

सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, बोले- 'तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है'

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसका मतलब १४० करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना है। इसके के लिए समस्त भारतवासियों को देश की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी बाइक रैलीश को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ महानगर की ओर से राष्ट्र प्रथम की भावना संग यह रैली निकाली गई। इसमें हजारों उत्साहित कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। योगी आदित्यनाथ ने आजादी के ७८वें

के नेतृत्व में एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। दो वर्ष पहले देश के आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन से जुड़कर हम लोगों ने पंच प्रण का संकल्प लिया था और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में श्हर घर तिरंगाश के माध्यम से भारत के आन–बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं। उन्होंने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर श्हर घर तिरंगाश अभियान के अंतर्गत शतिरंगा यात्रा स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि २०२२–२३ में उत्तर प्रदेश ने पांच करोघ्ड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी उत्तर प्रदेश में लगभग साढ़े चार करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को साढ़े चार करोड़ घरों तक पहुंचाने का वृहद संकल्प लिया है। भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प के साथ जुड़कर हम सभी भारत के आन–बान–शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के सहभागी बन रहे है। सीएम योगी ने कहा कि उप्र में पिछले तीन दिन के अंदर भाजपा के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें शामिल छात्र, व्यवसायी समेत अनेक सामाजिक–सांसेंतिक संगठनों के द्वारा दिख रहा उत्साह नए भारत का दर्शन कराता है। तिरंगा एक भारत–श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। सीएम ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आज से १५ अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने अपील की कि इसके साथ हम खुद भी जुड़ेंगे और हर प्रदेशवासी को जोड़ेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत माता की जयकार संग हाथ में तिरंगा फहराते अपने आवास से पैदल चले। सीएम ने राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम के भाव व पंच प्रण के संकल्पों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस दौरान ंषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, विध ान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी, विधायक नीरज बोरा, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की १७ से २२ अगस्त तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

लखनऊ। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम १७ से २२ अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने आवश्यक कलपुर्जों, असेम्बलीज की व्यवस्था पूरी कर शत–प्रतिशत बसों को अ न रोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि, विषम परिस्थिति को छोड़कर सभी अधि ाकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। बिना सूचना कोई भी अधिकारी कार्य स्थल नहीं छोड़ेगा। स्टापेज के अलावा बीच रास्ते पर मिलने वाले यात्रियों को भी बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। एमडी परिवहन निगम मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधकों को पूर्वी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसों का संचालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अनुबंधित बसों का संचालन करने के साथ कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के तहत लगाई जाए। भीड़ बढ़ने पर विभिन्न गंतव्यों विशेषकर लखनऊ और कानपुर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराया जाए। रक्षाबंधन के दूसरे दिन यात्री कम होने पर अतिरिक्त बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। एमडी ने बसों और बस अड्डों की साफ–सफाई, चेकिग दलों को सघन चेकिंग, ब्रेथ एनलाइजर से चालकों, परिचालकों की एल्कोहल जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि नियमित और संविदा चालकों, परिचालकों को १८०० किमी का संचालन पूरा करने पर १२०० रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। १८०० किलोमीटर से अधिक बस चलाने पर ५५ पैसे प्रति किमी की दर से अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। डिपो, क्षेत्रीय कार्यशाला के

तकनीकी कर्मचारियों को एकमुश्त ५०० रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन अवधि में योजना की प्रात्रता हेतु सेवा का लोड फैक्टर ६४ प्रतिशत अधिक होने पर संबंधित चालक,परिचालक को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लखनऊ, कानपुर,इटावा, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर बस स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। एमडी ने इन बस स्टेशनों पर आवश्कतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए हैं। बस स्टेशनों पर तैनात कार्मिकों और पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहन धनराशि के उद्देश्य से ५००० रुपये प्रति स्टेशन की दर से दिए जाएंगे।

नाम बदलकर युवती से की दोस्ती, दुष्कर्म के बाद बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

लखनऊ। मोहनलालगंज के पुरसेनी में रहने वाले युवक ने नाम बदलकर एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती से दोस्ती की। उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि शादी का झांसा दिया। इसके बाद उससे धर्म बदलने का दबाव बनाया। उसे प्रतिबंधित मांस खिलाया और रोजा रखने का दबाव बनाया। युवती ने युवक, उसके पिता और दोस्तों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आलमबाग में अपने पति के साथ रहने वाली २५ वर्षीय युवती ने मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर में कहा कि एक साल पहले वह एक प्राइवेट कम्पनी में काम करती थी। जहां पुरसेनी में रहने वाले अकील ने मेरा मोबाइल नम्बर हासिल कर लिया और अखिल यादव नाम से कॉल करने लगा और दोस्ती कर ली। आरोप है कि ८ दिसम्बर २०२३ को अकील, अपने पिता खलील व दोस्त इंतजार अहमद के साथ कैसरबाग कचहरी ले गए। जहां एक वकील ने कुछ कागजो में लिखा पढ़ी करवाई और उसके बाद अकील अपने घर लेकर आ गया। जहां अकील व उसके पिता खलील ने दुष्कर्म किया। १७ जनवरी को आरोपी उसे हरिकंशगढी में एक किराये का मकान लेकर आ गया जहां अकील के दोस्त इरफान, इन्तजार व एक अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया। २ जुलाई को आरोपी ने युवती की पिटाई कर भगा दिया, जिसके बाद युवती अपने पति के पास चली गई। आरोप है कि शुक्रवार को आरोपी ने कॉल कर मोहनलालगंज बुलाया। वहां एक बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। प्रभारी निरीक्षक आलोक राव के मुताबिक तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने में जन सहभागिता जरूरी : प्रशांत कुमार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में जनसहभागिता जरूरी है और इसके लिये आम लोगों को सतर्क एवं संवेदनशील रहना होगा। प्रशांत कुमार ने सोमवार को 'यूपी ११२' के विशेष अभियान 'एक पहल' की शुरुआत के मौके पर कहा कि 'एक पहल' सतर्कता, संवेदनशीलता, सहायता का अभियान है। यह आम लोगों को सतर्क, संवेदनशील बनाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस को लेकर कहा जाता कि

वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में व्यस्त रहती है लेकिन ट्रेनिंग, भर्ती हर आयाम में यूपी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। यूपी इस समय दस्यु मुक्त, फिरौती मुक्त है। आठ साल पहले यूपी ११२ का रिस्पॉन्स टाईम ४० – ४५ मिनट था जो अब ८ – ६ मिनट है। पुलिस महानिदेशक ने आम लोगों से अपील करते हुये कहा कि वे संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु की सूचना यूपी ११२ को देने में संकोच न करें। छेड़छाड़, छींटाकशी, सड़क पर पड़े घायल की अनदेखी न करें। किसी दूसरे को भी मुसीबत में देखकर उसका वीडियो बनाने की बजाय यूपी ११२ कॉल करें।

पाकिस्तानी वाट्सएप कॉल से मांगी फिरौती

लखनऊ। निगोंहा थाना अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज की छात्राओं के परिजनों के मोबाइल पर पाकिस्तान के नम्बर से वाट्सएप क ल आई। फोनकर्ता न छात्राओं के अपहरण की सूचना देते हुए परिजनों से फिरौती मांगी। घबराए परिजन फौरन क लेज पहुंचे और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया है। फिर सर्विलांस की मदद से फोनकर्ता की लोकेशन खंगालनी शुरु कर दी है। प्रभारी निरीक्षक अनुज तिवारी ने बताया कि मंगलवार सुबह क्षेत्र के गंगादेवी डिग्री कॉलेज की कई छात्राओं के परिजनों के मोबाइल पर उनके अपहरण की सूचना दी गई थी। फोनकर्ता ने ६२–३४१०२७४११५ से परिजनों को वाट्सएप क ल की थी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम ष्या में पता चला कि ६२ की शुरुआत पाकिस्तान के नंबरों में होती है। इसी बीच एक अभिभावक ने बताया कि उनकी बेटी डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, उनके पास वाट्सएप कॉल आई, फोनकर्ता ने बेटी नगमा को अपने चंगुल से छोड़ने के लिए रुपयो की मांग की। बताया कि फोनकर्ता की वाट्सएप डीपी पर किसी अधि ाकारी की फोटो लगी है। फोनकर्ता की बात सुनकर पीड़ित फौरन डिग्री कॉलेज पहुंचा, जहां बेटी स्कूल में सुरक्षित मिली। इसके बाद पीड़ित ने कॉलेज प्रशासन को पूरी दास्तां सुनाई। इसी तरह से फोनकर्ता ने छात्रा अंकिता, नैंसी के परिजनों को वाट्सएप कॉल कर फिरौती मांगी है।

हर गांव में जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जल जीवन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन बिछाने के साथ ही संचालन और रखरखाव को लेकर भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल जीवन मिशन में हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के काम में प्लंबर की भूमिका को सबसे अहम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लंबरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में उपयोग की जा रही सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। पाइप, नल आदि की क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो। टोटी चोरी होने या खराब होने पर तत्काल नई टोटी की व्यवस्था कराई जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में दो करोड़ ६३ लाख से अधिक घरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें १.६० लाख करोड़ रुपये लागत आ रही है। प्रतिवर्ष इसके संचालन और रखरखाव में करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पेयजल अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा तो उन्हें विभिन्न बीमारियों से निजात मिलेगी, जिससे हमारे गांव स्वस्थ होंगे। यह योजना एक

प्रकार से वॉटर थेरेपी की तरह है, जिससे पाचन संबंधित, यूरीन संबंधित, पीलिया, किडनी की पथरी और किडनी फेल होने जैसी बीमारियों से काफी हद तक निजात मिलेगी। जल जीवन मिशन के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। इसके लिए ग्राम प्रधान के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल के लिए ग्रामीणों तक यह बात पहुंचाई जानी चाहिए कि उनके मोबाइल के मासिक खर्च से भी कम में उन्हें यह सुविधा दी जा रही है। इसके लिए पंचायत सहायक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) सखियों को भी लगाया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क को समय पर ठीक कराएं। प्रदेश के प्रत्येक गांव को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव के ऐसे तालाब जो किसी मंदिर से न जुड़े हों उनमें मत्स्य पालन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इसके अलावा ग्राम हाट और पक्की दुकानें बनाकर आय अर्जित की जा सकती है। इसके लिए अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री भी गांवों में जाएं और प्रधान तथा ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ग्राम सचिवालय का मॉडल पूरे देश को आकर्षित कर रहा है। यह गांव की समस्याओं के समाधान का माध्यम बना है। जिन कार्यों के लिए पहले तहसील जाना होता था, अब ग्रामीणों को वह सुविधा गांव में ही मिल रही है।

स्त्री–२ रिलीज से पहले बड़ा धमाका, राजकुमार के अंदाज ने बढ़ाया उत्साह

मुंबई। सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फिल्म स्त्री अपने पहले सीजन से ही सुर्खियों में है. अब इसका सीक्वल स्त्री–२ भी खूब चर्चा में है. रिलीज से पहले ही मूवी ने भारी भरकम कमाई कर ली है. राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म का उत्साह चरम पर है. अब स्त्री–२ १४ अगस्त को रिलीज होने वाली है. यह फिल्म पहले १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट चेंज कर दी. मेकर्स ने रिलीज डेट बदलने का कारण दिया वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है. मूवी की एडवांस बुकिंग जारी है. इसी

बीच निर्माताओं ने दर्शकों को लुभाने के लिए एक खास काउंटडाउन पोस्ट किया है, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं. दर्शक २०१८ की हिट स्त्री के सीक्वल स्त्री २ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने राजकुमार राव के एक नए, दिलचस्प पोस्टर के साथ प्रत्याशा की आग बढ़ा दी है. इस नए पोस्टर में राव अपने हाथों से दिल का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार के आकर्षण और रहस्य को दर्शाता है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'जे टेलर है, जे आशिक है अरे जे तो चंदेरी के राजकुमार हैं.इस आकर्षक पोस्टर ने फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है, जो सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. हालांकि, जो लोग १५ अगस्त का इंतजार नहीं कर सकते उनके लिए विशेष सीमित रात्रि शो १४ अगस्त को रात ६:३० बजे से उपलब्ध होंगे. स्त्री २ में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक, पंकज त्रिपाठी और अपारशक्ति खुराना ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस बार 'स्त्री २' में चंदेरी के निवासी एक नए राक्षस से लड़ने के मिशन पर दिखाई देंगे. फिल्म के निर्देशन की कमान अमर कौशिक ने संभाली है।

कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाना मेरे लिए बड़ा सम्मानः सिद्धार्थ मल्होत्रा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की ब्लॉकबस्टर फिल्म "शेरशाह" को तीन साल पूरे हो गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म के तीन साल पूरे होने पर खुशी जताई और कहा, "कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाना मेरे करियर के पुरस्ंत अनुभवों में से एक है। सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर फिल्म शेरशाह के सेट से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा की फोटो को शेयर किया है और एक तस्वीर में वह कियारा आडवाणी के साथ दिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा शेरशाह को तीन साल हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाना मेरे करियर के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक रहा, पर्दे पर एक महान नायक की कहानी को जीवंत किया गया। नतीजतन ६६वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल जूरी अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने आगे कहा उनके परिवार से मिलना इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। एक असली नायक की विरासत और हमने जो यादें संजोई उसका जश्न मनाने के लिए यहां है। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह, २०२१ में ओटीटी पर रिलीज हुई थी। फिल्म "शेरशाह" एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है। इसे विष्णुवर्धन ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा

के जीवन पर आधारित है। सिद्धार्थ ने इस फिल्म में डबल रोल निभाया है। फिल्म में कियारा आडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा का किरदार निभाया था। ६७वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित १६ नामांकन मिले। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ मेल गायक और सर्वश्रेष्ठ महिला गायक सहित सात पुरस्कार जीते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और कियारा की डेट करने की अफवाहों ने भी सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों के बीच प्यार फिल्म के सेट पर परवान चढ़ा और उन्होंने २०२३ में राजस्थान में शादी कर ली। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को आखिरी बार स्क्रीन पर एक्शन थ्रिलर "योद्धा" में देखा गया। इसमें उनके साथ राशि खन्ना और दिशा पटानी भी नजर आए।

तिरुमाला मंदिर में जान्हवी कपूर ने टेका मत्था

मुंबई। श्रीदेवी की जयंती पर उनकी बेटी और एक्ट्रेस जान्हवी कपूर तिरुमाला पहुंचीं। उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी साथ दिखे। दोनों ने यहां श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लिया। जान्हवी साउथ इंडियन लुक में नजर आईं। उन्होंने ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पीली रंग की साड़ी पहनी थी। वहीं कानों में झुमके, नेकलेस और कमरबंद उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। उन्होंने लुक को पूरा करने के लिए बालों का जुड़ा बनाया था। वहीं शिखर सफेद रंग की वेष्टि यानी

धोती में दिखे। उन्होंने अंगवस्त्र भी डाल रखा था। शिखर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं। जान्हवी और शिखर काफी समय से रिलेशनशिप में हैं। मंदिर में जान्हवी के लिए दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। दर्शन के बाद, टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के अधिकारियों ने उन्हें भगवान वेंकटेश्वर के रंगनायक मंडपम में रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया और भगवान का प्रसाद दिया। दरअसल, आज उनकी मां और बॉलीवुड की बड़ी अदाकारा श्रीदेवी की ६१ वीं जयंती है। जान्हवी हर बार मां के जन्मदिन पर तिरुपति बाला जी दर्शन करने जाती हैं। एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो जान्हवी कपूर सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'देवरा' के जरिए साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इस फिल्म से ब लीवुड एक्टर सैफ अली खान भी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा, वह सस्पेंस–थ्रिलर 'उलझ' को लेकर भी चर्चाओं में हैं, जिसको दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lt; ckt ibl

lhrkiqj

ek-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

ljs'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

ek-09386075289

मो० अरशद

C;wjks phQ

eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक